



SAFALTA CLASSTM

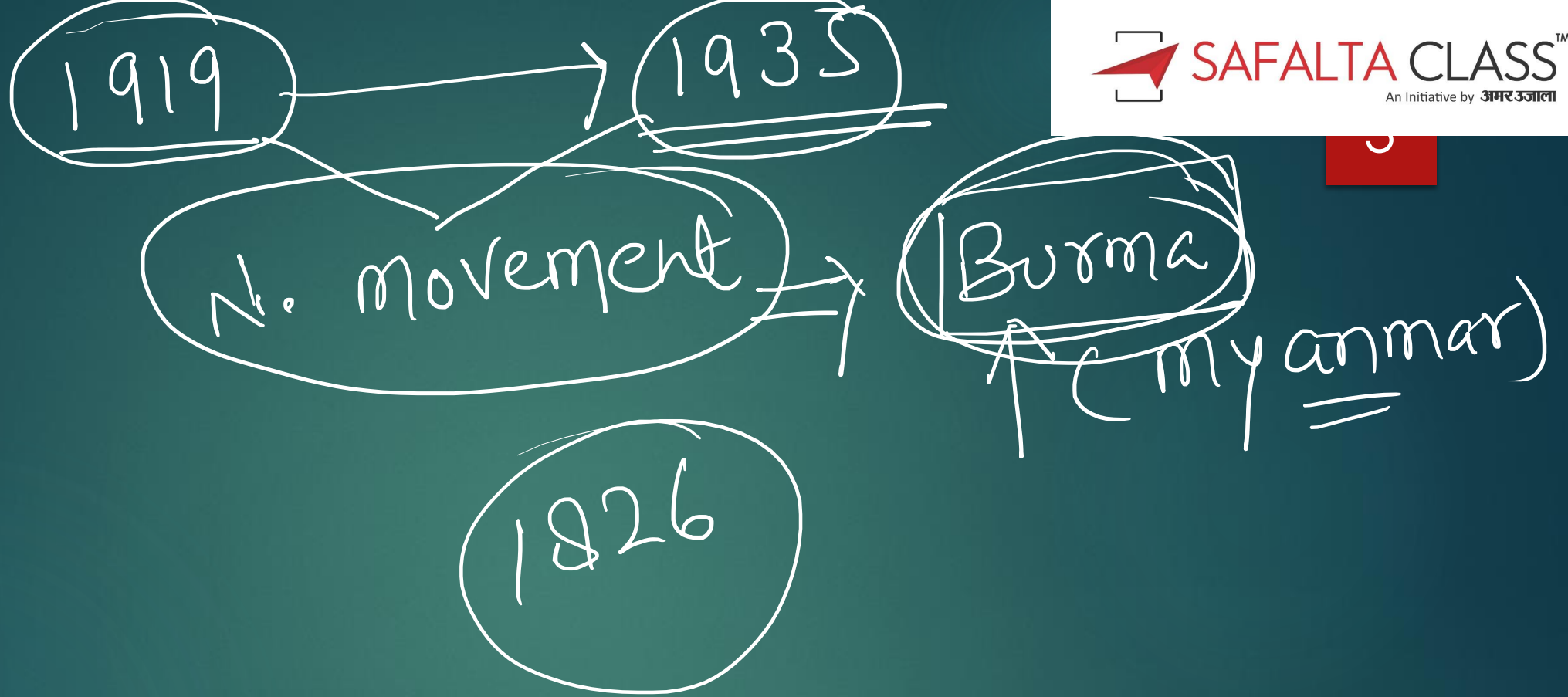
An Initiative by **अमरउजाला**

INDIAN

POLITY

BY – SUJEET BAJPAI SIR





Morris Gyfe

संघीय न्यायक

Government of India Act of 1935

Fed. Court

The Act marked a second milestone towards a completely responsible government in India.

It was a lengthy and detailed document having 321 Sections and 10 Schedules.

SC Fed. Court

भारत सरकार अधिनियम 1935

- ❖ यह अधिनियम भारत में पूरी तरह से जिम्मेदार सरकार की दिशा में एक दूसरा मील का पत्थर है ।
- ❖ यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था जिसमें ३२१ धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं ।

अखिल भारतीय संघ

1.

It provided for the establishment of an All-India Federation consisting of provinces and princely states as units.

The Act divided the powers between the Centre and units in terms of three lists—

Federal List (for Centre, with 59 items), Provincial List (for provinces, with 54 items) and the Concurrent List (for both, with 36 items). Residuary powers were given to the Viceroy.

7

1.

इसमें प्रांतों और रियासतों को इकाइयों के रूप में मिलाकर अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना की व्यवस्था की गई थी।

इस अधिनियम ने तीन सूचियों के हिसाब से केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया- संघीय सूची (केंद्र के लिए, ५९ मदों के साथ), प्रांतीय सूची (प्रांतों के लिए, ५४ मदों के साथ) और समवर्ती सूची (दोनों के लिए, ३६ मदों के साथ)।
वायसराय को आण-नाता दिया गया।

However, the federation never came into being as the princely states did not join it.

2. It abolished dyarchy in the provinces and introduced 'provincial autonomy' in its place.

1919

start

1935

end

हालांकि, फेडरेशन कभी अस्तित्व में नहीं आया क्योंकि रियासतों ने इसमें शामिल नहीं किया ।

2. प्रांतों में डायसत्ता को समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर ' प्रांतीय स्वायत्तता ' शुरू की ।

2. 

1765 | 1784

It provided for the adoption of dyarchy at the Centre. Consequently, the federal subjects were divided into reserved subjects and transferred subjects.

However, this provision of the Act did not come into operation at all.

2.

इसमें केंद्र में ~~हस्त~~सत्ता को गोद लेने की व्यवस्था की गई थी।

नतीजतन, संघीय विषयों को आरक्षित विषयों और स्थानान्तरित विषयों में विभाजित किया गया था।

हालांकि एक्ट का यह प्रावधान बिल्कुल भी लागू नहीं हुआ।

3.

It provided for the establishment of a Reserve Bank of India to control the currency and credit of the country.

4.

It provided for the establishment of not only a Federal Public Service Commission but also a Provincial Public Service Commission and Joint Public Service Commission for two or more provinces.

3.

इसमें देश की मुद्रा और ऋण को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान किया गया था।

4.

इसमें न केवल संघीय लोक सेवा आयोग बल्कि दो या अधिक प्रांतों के लिए प्रांतीय लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान था।

5.

It provided for the establishment of a Federal Court, which was set up in 1937.

5.

इसमें संघीय अदालत की स्थापना का प्रावधान था, जिसकी स्थापना १९३७ में की गई थी ।

Indian Independence Act of 1947

1.

It ended the British rule in India and declared India as an independent and sovereign state from August 15, 1947.

2.

It provided for the partition of India and creation of two independent dominions of India and Pakistan with the right to secede from the British Commonwealth.

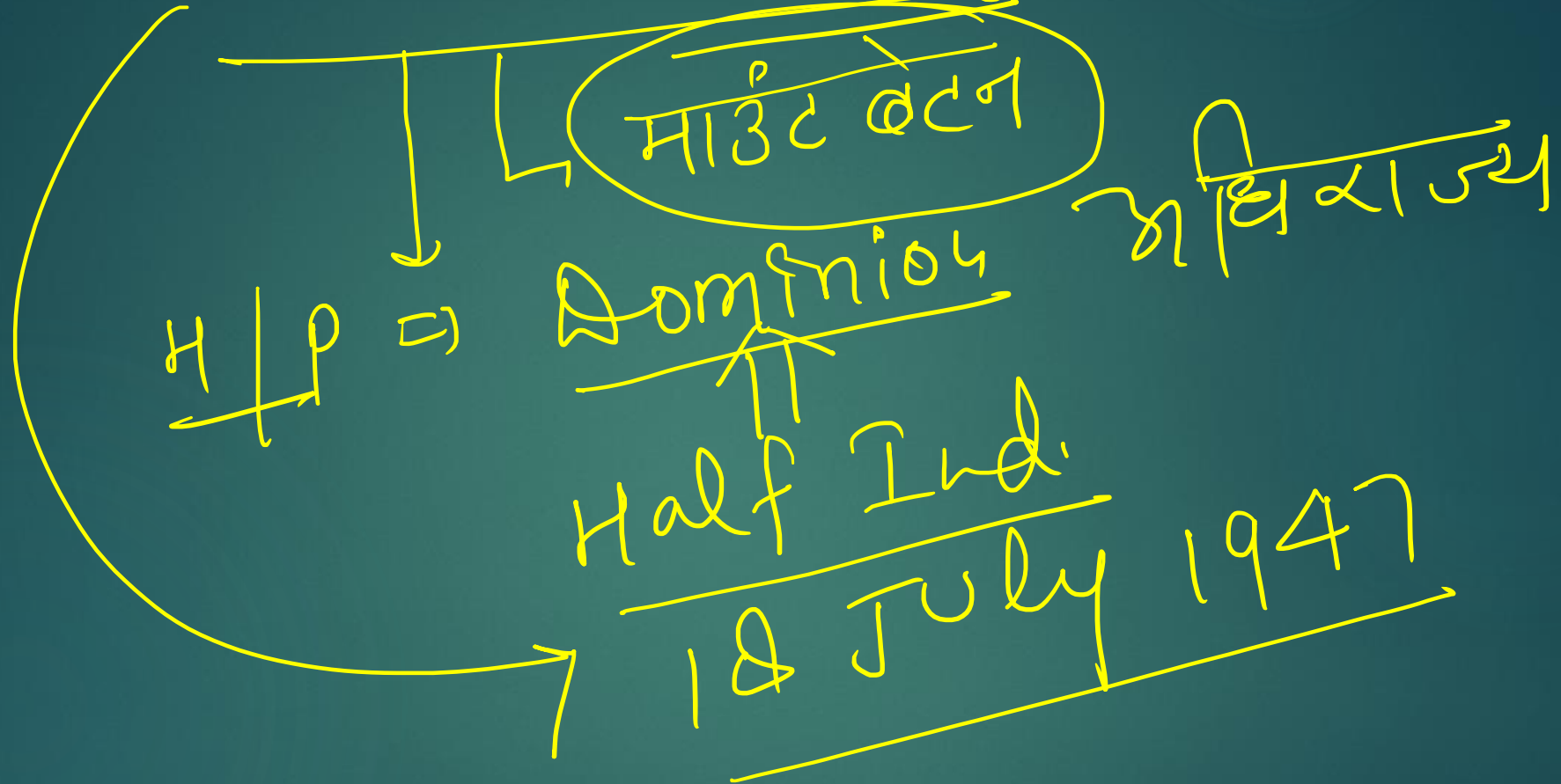
1947 — 1950

II 21147

G.O.I. v 1935

→ संविधान के लगातार
द्वारा शामिल है।

[3rd June plan] =



1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम

1.

इसने भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त कर दिया और 15 अगस्त, 1947 से भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित कर दिया।

2.

इसमें भारत के विभाजन और ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने के अधिकार के साथ भारत और पाकिस्तान के दो स्वतंत्र प्रभुत्व के निर्माण का प्रावधान था।

3.

It abolished the office of viceroy and provided, for each dominion, a governor-general, who was to be appointed by the British King on the advice of the dominion cabinet.

His Majesty's Government in Britain was to have no responsibility with respect to the Government of India or Pakistan.

3.

इसने वायसराय के पद को समाप्त कर दिया और प्रत्येक प्रभुत्व के लिए एक गवर्नर-जनरल, जो प्रभुत्व के कबिनेट की सलाह पर ब्रिटिश राजा द्वारा नियुक्त किया जाना था, प्रदान किया।

ब्रिटेन में महामहिम की सरकार को भारत सरकार या पाकिस्तान के संबंध में कोई जिम्मेदारी नहीं निभानी थी।

1947

4.

It empowered the Constituent Assemblies of the two dominions to frame and adopt any constitution for their respective nations and to repeal any act of the British Parliament, including the Independence act itself.

इसने दोनों देशों की संविधान सभाओं को अपने-अपने राष्ट्रों के लिए किसी भी संविधान को तैयार करने और अपनाने और स्वतंत्रता अधिनियम सहित ब्रिटिश संसद के किसी भी अधिनियम को निरस्त करने का अधिकार दिया ।

1885

5.

It empowered the Constituent Assemblies of both the dominions to legislate for their respective territories till the new constitutions were drafted and enforced.

No Act of the British Parliament passed after August 15, 1947 was to extend to either of the new dominions unless it was extended thereto by a law of the legislature of the dominion.

5.

इसने दोनों देशों की संविधान सभाओं को नए संविधानों का मसौदा तैयार करने और लागू होने तक अपने-अपने क्षेत्रों के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया ।

15 अगस्त, १९४७ के बाद पारित ब्रिटिश संसद का कोई अधिनियम नए डोमिनरों में से किसी को भी तब तक विस्तारित नहीं करना था जब तक कि इसे प्रभुत्व की विधायिका के कानून द्वारा नहीं बढ़ाया गया था ।

6.

It abolished the office of the secretary of state for India.

7.

It proclaimed the lapse of British paramountcy over the Indian princely states.

अधिलक्षणा

6.

इसने भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद समाप्त कर दिया ।

7.

इसने भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोपरिता की चूक की घोषणा की ।

8.

It granted freedom to the Indian princely states either to join the Dominion of India or Dominion of Pakistan or to remain independent.

9.

It provided for the governance of each of the dominions and the provinces by the Government of India Act of 1935, till the new Constitutions were framed.

The dominions were however authorised to make modifications in the Act.

8.

इसने भारतीय रियासतों को या तो भारत के प्रभुत्व में शामिल होने या पाकिस्तान के डोमिनर में शामिल होने या स्वतंत्र रहने की आजादी दी ।

9.

इसमें 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रत्येक डोमिनेशन और प्रांतों के शासन का प्रावधान किया गया था, जब तक कि नए संविधान नहीं बन जाते । हालांकि इस अधिनियम में संशोधन करने के लिए डोमिनेशन को अधिकृत किया गया था ।

10.

It deprived the British Monarch of his right to veto bills or ask for reservation of certain bills for his approval.

इसने ब्रिटिश सम्राट को विधेयकों को वीटो करने के अपने अधिकार से वंचित कर दिया या उनकी मंजूरी के लिए कुछ विधेयकों के आरक्षण की मांग की ।

इतिहास सर्ग

> 1895 = B. G. Tilak

> 1928 = Nehru Report
(Motilal)

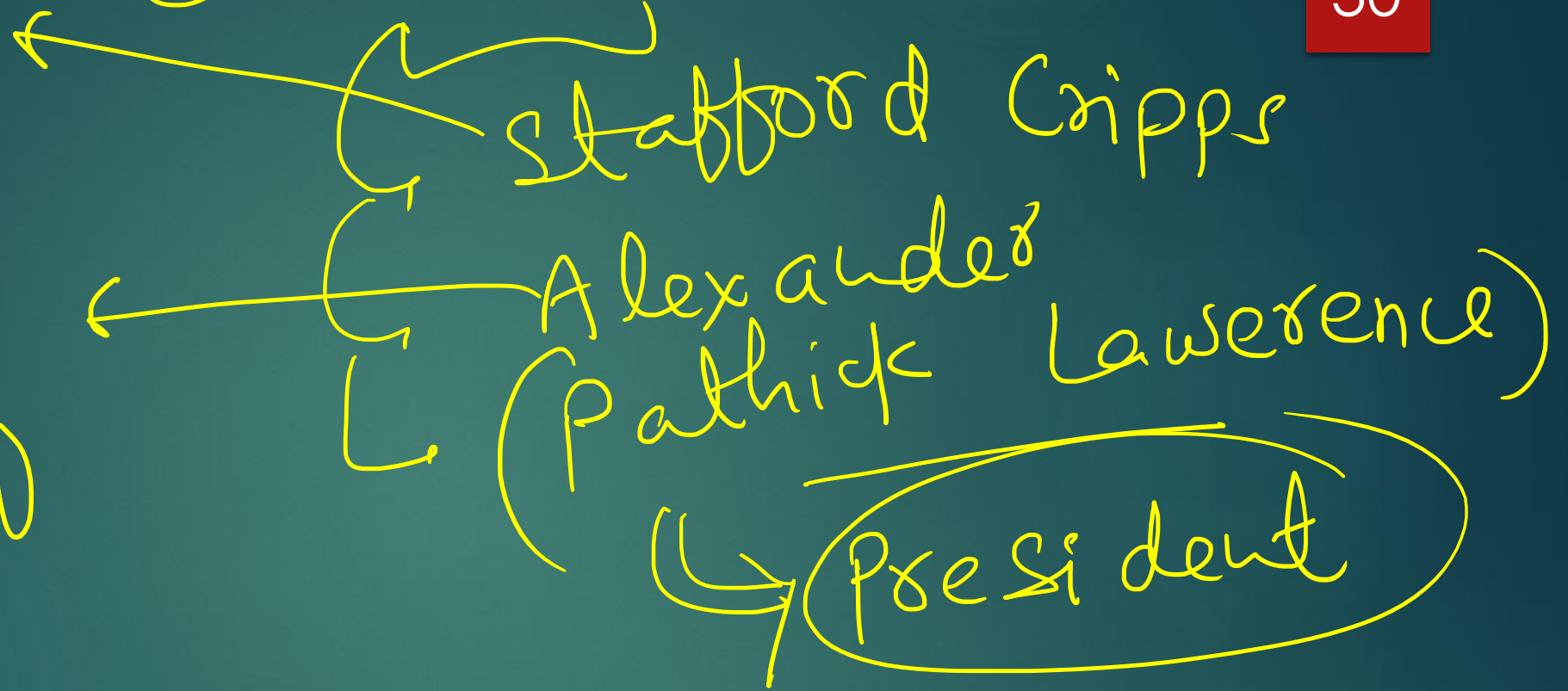
> 14 point formula by Jinnah.
m. N. Roy = Communist
leader

>

Cabinet
min

Cabinet mission

Navy
chief



10 लक्षा = 1 member

Constituent Assembly

It was in 1934 that the idea of a Constituent Assembly for India was put forward for the first time by M. N. Roy, a pioneer of communist movement in India.

1934 में भारत के लिए संविधान सभा का विचार भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के पुरोधा एमएन रॉय ने पहली बार सामने रखा था।

In 1935, the Indian National Congress (INC), for the first time, officially demanded a Constituent Assembly to frame the Constitution of India.

The demand was finally accepted in principle by the British Government in what is known as the 'August Offer' of 1940.

In 1942, Sir Stafford Cripps, a member of the cabinet, came to India with a draft proposal of the British Government on the framing of an independent Constitution to be adopted after the World War II.

1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (कांग्रेस) ने पहली बार आधिकारिक तौर पर भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की मांग की थी।

इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया जिसे १९४० के 'अगस्त ऑफर' के रूप में जाना जाता है।

1942 में मंत्रिमंडल के सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अपनाए जाने वाले स्वतंत्र संविधान के निर्माण पर ब्रिटिश सरकार के मसौदा प्रस्ताव के साथ भारत आए थे।

The Cripps Proposals were rejected by the Muslim League which wanted India to be divided into two autonomous states with two separate Constituent Assemblies.

Finally, a Cabinet Mission was sent to India. While it rejected the idea of two Constituent Assemblies, it put forth a scheme for the Constituent Assembly.

क्रिप्स प्रस्तावों को मुस्लिम लीग ने खारिज कर दिया था जो चाहता था कि भारत को दो अलग संविधान सभाओं के साथ दो स्वायत्त राज्यों में बांटा जाए ।

अंत में, एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया।

हालांकि इसने दो संविधान सभाओं के विचार को अस्वीकार कर दिया, लेकिन इसने संविधान सभा के लिए एक योजना प्रस्तुत की ।

British Ind.

389 members

296

93

Provinces

States

292

4

चौह
अजमेरी

A -

Ajmer

B -

Balochistan

C -

Delhi

D -

अन्दा
Coorg

Composition of The Constituent Assembly:

The Constituent Assembly was constituted in November 1946 under the scheme formulated by the Cabinet Mission Plan. The features of the scheme were:

संविधान सभा की संरचना:

संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना द्वारा बनाई गई योजना के तहत नवंबर 1946 में किया गया था। योजना की विशेषताएं थीं:

1.

The total strength of the Constituent Assembly was to be 389, of these, 296 seats were to be allotted to British India and 93 seats to the Princely States.

Out of 296 seats allotted to the British India, 292 members were to be drawn from the eleven governors' provinces² and four from the four chief commissioners' provinces³, one from each.

1. संविधान सभा की कुल संख्या 389 होनी थी, इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत को और 93 सीटें रियासतों को आवंटित की जानी थीं।

ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 सदस्यों को ग्यारह राज्यपालों के प्रांतों से 2 और चार मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से चार, प्रत्येक से एक तैयार किया जाना था ।

2.

Roughly, one seat was to be allotted for every million population.

3.

Seats allocated to each British province were to be divided among the three principal communities—Muslims, Sikhs and general (all except Muslims and Sikhs), in proportion to their population.

2. मोटे तौर पर हर दस लाख की आबादी के लिए एक सीट आवंटित की जानी थी।

3. प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित सीटों को उनकी आबादी के अनुपात में तीन प्रमुख समुदायों-मुस्लिमों, सिखों और सामान्य (मुसलमानों और सिखों को छोड़कर) के बीच विभाजित किया जाना था ।

<i>Sl.No.</i>	<i>Name of the Party</i>	<i>Seats won</i>
1.	Congress	208
2.	Muslim League	73
3.	Unionist Party	1
4.	Unionist Muslims	1
5.	Unionist Scheduled Castes	1
6.	Krishak – Praja Party	1
7.	Scheduled Castes Federation	1
8.	Sikhs (Non-Congress)	1
9.	Communist Party	1
10.	Independents	8
Total		296

डिप्टी Interim
Cabinet

Sl. No.	Members	Portfolios Held
1.	Jawaharlal Nehru	Prime Minister; External Affairs & Commonwealth Relations; Scientific Research
2.	Sardar Vallabhbhai Patel	Home, Information & Broadcasting; States
3.	Dr. Rajendra Prasad	Food & Agriculture
4.	Maulana Abul Kalam Azad	Education
5.	Dr. John Mathai	Railways & Transport
6.	R.K. Shanmugham Chetty	Finance
7.	Dr. B.R. Ambedkar	Law
8.	Jagjivan Ram	Labour
9.	Sardar Baldev Singh	Defence

पहली महिला के मंत्री

10.

Raj Kumari Amrit
Kaur

Health

==

11.

C.H. Bhabha

Commerce

12.

Rafi Ahmed Kidwai

Communication

13.

Dr. Shyam Prasad
Mukherji

Industries & Supplies

14.

V.N. Gadgil

Works, Mines & Power

संविधान
सूची
15 महिलाएं

भारतीय संविधान सभा में शामिल महिला सदस्य

15

1. विजयलक्ष्मी पंडित	9. कमला चौधरी
2. राजकुमारी अमृत कौर	10. रेणुका रॉय
3. सरोजिनी नायडू	11. मालती चौधरी
4. सुचेता कृपलानी	12. दक्षयानी वेलायुदन
5. पूर्णिमा बनर्जी	13. बेगम एजाज रसूल
6. लीला राय	14. ऐनी मस्करीनी
7. जी दुर्गाबाई	15. अम्मू स्वामीनाथन
8. हंसा मेहता	

Note: The Assembly included all important personalities of India at that time, with the exception of Mahatma Gandhi.

& Jinnah
==

नोट- विधानसभा में उस समय भारत की सभी महत्वपूर्ण हस्तियां शामिल थीं, जिनमें महात्मा गांधी को छोड़ दिया गया था।

Working of the Constituent Assembly

The Constituent Assembly held its first meeting on December 9, 1946. The Muslim League boycotted the meeting and insisted on a separate state of Pakistan.

1919

Central Hall

(संविधान सभा)

संविधान सभा का कार्य संविधान सभा ने अपनी पहली बैठक 9 दिसंबर, 1946 को आयोजित की थी। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार करते हुए अलग राज्य पाकिस्तान पर जोर दिया।

The meeting was thus attended by only 211 members. Dr Sachchidanand Sinha, the oldest member, was elected as the temporary President of the Assembly, following the French practice.

Later, Dr. Rajendra Prasad was elected as the President of the Assembly. Similarly, both H.C. Mukherjee and V.T. Krishnamachari were elected as the Vice-Presidents of the Assembly. In other words, the Assembly had two Vice-Presidents.

इस तरह बैठक में केवल 211 सदस्यों ने भाग लिया।

सबसे उम्रदराज सदस्य डॉ सच्चिदानंद सिन्हा को विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया ।

बाद में डॉ राजेंद्र प्रसाद को विधानसभा अध्यक्ष चुना गया।

इसी तरह एचसी मुखर्जी और वीटी कृष्णमाचारी दोनों को विधानसभा का उपाध्यक्ष चुना गया।

दूसरे शब्दों में, विधानसभा में दो उपाध्यक्ष थे ।

Objectives Resolution

Base

On December 13, 1946, Jawaharlal Nehru moved the historic 'Objectives Resolution' in the Assembly.

This Resolution was unanimously adopted by the Assembly on January 22, 1947. Its modified version forms the Preamble of the present Constitution.

Preamble
३६६ (२१९१)

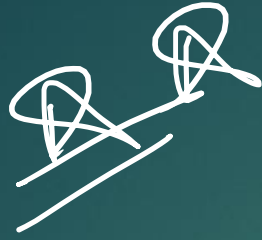
उद्देश्य संकल्प

13 दिसंबर, 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने विधानसभा में ऐतिहासिक 'उद्देश्य संकल्प' पेश किया।

इस प्रस्ताव को विधानसभा ने 22 जनवरी, 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया था।

इसका संशोधित संस्करण वर्तमान संविधान की प्रस्तावना है ।

Functions:



1.

It ratified the India's membership of the Commonwealth in May 1949.

2.

It adopted the national flag on July 22, 1947.

3.

It adopted the national anthem on January 24,
1950.

कार्यो:

1. इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि की थी।
2. इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था।
3. इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया था।

4.

It adopted the national song on January 24, 1950.

5.

It elected Dr Rajendra Prasad as the first President of India on January 24, 1950.

In all, the Constituent Assembly had 11 sessions over two years, 11 months and 18 days.

3 Times

1

2

11

C.A

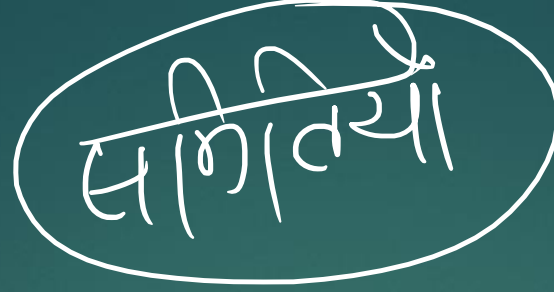
11

18

2

4. इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को अपनाया।

5. इसने 24 जनवरी, 1950 को डॉ राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना। कुल मिलाकर संविधान सभा में दो साल, 11 महीने और 18 दिन में 11 सत्र हुए ।



Major Committees

1. Union Powers Committee – Jawaharlal Nehru
2. Union Constitution Committee – Jawaharlal Nehru
3. Provincial Constitution Committee – Sardar Patel
4. Drafting Committee – Dr. Ambedkar

प्रमुख समितियां

1. केंद्रीय अधिकार समिति - जवाहरलाल नेहरू
2. संघ संविधान समिति - जवाहरलाल नेहरू
3. प्रांतीय संविधान समिति - सरदार पटेल
4. ~~ड्राफ्टिंग कमेटी - डॉ. अंबेडकर~~

5. Advisory Committee on Fundamental Rights, Minorities and Tribal and Excluded Areas – Sardar Patel.

6. Rules of Procedure Committee – Dr. Rajendra Prasad


7. States Committee (Committee for Negotiating with States) – Jawaharlal Nehru

8. Steering Committee – Dr. Rajendra Prasad

5. मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति - सरदार पटेल।

6. प्रक्रिया समिति के नियम - डॉ राजेंद्र प्रसाद

7. राज्य समिति (राज्यों के साथ बातचीत के लिए समिति) - जवाहरलाल नेहरू

 8. संचालन समिति - डॉ राजेंद्र प्रसाद

Minor Committees

1. Finance and Staff Committee – Dr. Rajendra Prasad
2. Credentials Committee – Alladi Krishnaswami Ayyar
3. House Committee – B. Pattabhi Sitaramayya

छोटी समितियां

1. वित्त एवं कर्मचारी समिति - डॉ राजेंद्र प्रसाद
2. साख समिति - अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर
3. सभा समिति - बी पट्टाभि सीतारामैया

4. Order of Business Committee – Dr. K.M. Munshi

5. Ad-hoc Committee on the National Flag – Dr. Rajendra Prasad

6. Committee on the Functions of the Constituent Assembly – G.V. Mavalankar

7. Ad-hoc Committee on the Supreme Court – S. Varadachari (Not an Assembly Member)

4. व्यापार समिति का आदेश - डॉ. केएम मुंशी
5. राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति - डॉ राजेंद्र प्रसाद
6. संविधान सभा के कार्यों पर समिति - जीवी मावलंकर
7. सुप्रीम कोर्ट पर तदर्थ समिति - एस वरदाचारी
(विधानसभा सदस्य नहीं)

Drafting Committee

ड्राफ्टिंग कमिटी

Among all the committees of the Constituent Assembly, the most important committee was the Drafting Committee set up on August 29, 1947. It was this committee that was entrusted with the task of preparing a draft of the new Constitution.

B. N. Rao

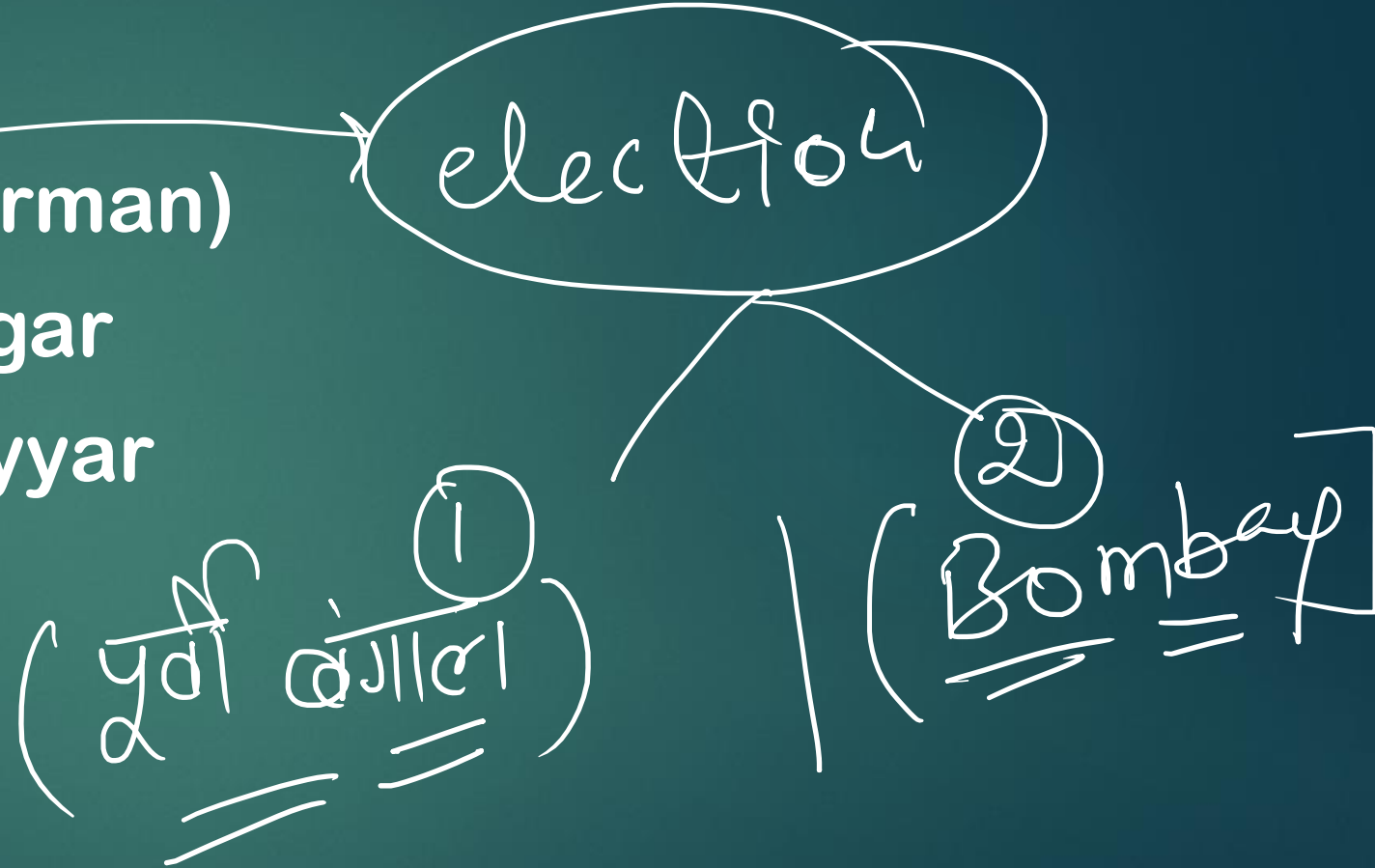
संविधान के मसौदाकर्ता

ड्राफ्टिंग कमेटी

संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति 29 अगस्त, 1947 को गठित ड्राफ्टिंग कमेटी थी। यह वह समिति थी जिसे नए संविधान का मसौदा तैयार करने का काम सौंपा गया था ।

It consisted of seven members. They were:

1. Dr B R Ambedkar (Chairman)
2. N Gopalaswamy Ayyangar
3. Alladi Krishnaswamy Ayyar
4. Dr K M Munshi



इसमें सात सदस्य शामिल थे। वो थे:

1. डॉ बी आर अंबेडकर (अध्यक्ष)
2. एन गोपालस्वामी अयंगर
3. अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर
4. डॉ के एम मुंशी

5. Syed Mohammad Saadullah

6. N Madhava Rau (He replaced B L Mitter who resigned due to ill-health)

7. T T Krishnamachari (He replaced D P Khaitan who died in 1948)

5. सैयद मोहम्मद सादुल्लाह
6. एन माधव राऊ (उन्होंने बी एल मिटर की जगह ली जिन्होंने खराब स्वास्थ्य के कारण इस्तीफा दे दिया)
7. टी टी कृष्णमाचारी (उन्होंने डी पी खेतान की जगह ली जिनकी मृत्यु 1948 में हुई थी)